भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2584

11 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कुछ राज्यों में सहकारिता ढांचे को सुदृढ़ किया जाना

2584. डा. नरेन्द्र जाधव:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सहकारिता ढांचे को सुदृढ़ करने का कोई विचार रखती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उपर्युक्त राज्यों में सहकारिता ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और 'सहकारिता से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए जीवंत सहकारी आंदोलन वाले सभी क्षेत्रों में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विनिर्दिष्ट योजनाएँ, सेक्टर की आवश्यकता के अनुसार सामने आएंगी। देश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश का एक अभिन्न अंग है।

(ख) कृषि सहकारिता पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) के तहत सहकारी समितियों के विकास के लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद(एनसीसीटी) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। आईएसएसी के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान एनसीडीसी को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)
2016-17	11,295.00
2017-18	20,181.00
2018-19	11,450.00
2019-20	12,950.00
2020-21	31,139.00

इन निधियों का उपयोग बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित पूरे देश में सहकारी समितियों को राजसहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।

******